RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 167
दि. 16.10.2025,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : ASHWANI KUMAR Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

संक्षिप्त समाचार

प्रधानमंत्री ने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।

श्री मोदी ने कहा कि डॉ. कलाम को एक दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने युवा मन को जागृत किया और राष्ट्र को बड़े स्वप्न देखने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ. कलाम का जीवन हमें स्मरण कराता है कि सफलता के लिए विनम्रता और अथक परिश्रम आवश्यक है।

प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि हम डॉ. कलाम के सपनों के अनुरूप एक सशक्त, आत्मनिर्भर और करूणामय भारत का निर्माण करना जारी रखेंगे।

'एकजुट एनडीए-एकजुट बिहार' पीएम मोदी ने दिया बिहार चुनाव का नारा, कहा- घर-घर पहुंचाएं बूथ वर्कर्स

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 'एकजुट NDA, एकजुट बिहार, फिर से बनेगी सुशासन की सरकार'का नारा दिया है. उन्होंने बीजेपी कार्यकताओं को हर बूथ और हर घर तक पहुंचने की हिदायत दी. उन्होंने बूथ वर्कर्स को सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बिहार में बीजेपी कार्यकताओं से कहा कि वे घर घर जाएं और केंद्र एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दें. उन्होंने ये यहां नया नारा दिया कि 'एकजुट ठऊअ, एकजुट बिहार, फिर से बनेगी सुशासन की सरकार'. अब देखना ये है कि बिहार में ये नारा क्या रंग लाता है. बूथ वर्कर्स को इस नारे को हर किसी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

मोदी ने नमो ऐप के माध्यम से चुनावी राज्य के बीजेपी कार्यकताओं से बातचीत करते हुए ये भी जोर दिया कि हर बूथ को मजबूत बनाना जरूरी है ताकि पार्टी की जीत सुनिश्चित हो सके. उन्होंने कार्यकताओं को

प्रोत्साहित किया कि वे अपने इलाके के हर परिवार को उपलब्ध सरकारी लाभ और योजनाओं के बारे में जानकारी दें. कार्यकताओं का उत्साह बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने कई वाक्य भोजपुरी में भी बोले. लोगों को वीडियो दिखाएं और शेयर करेंए मोदी ने भोजपुरी में कार्यकताओं से कहा कि 'जब हर बूथ मजबूत होगा, तभी पार्टी जीतती है'. पीएम ने ये भी कहा कि 'हर बूथ वर्कर अपने क्षेत्र में मोदी हैं' और उन्हें मतदाताओं को सरकारी योजनाओं के बारे में अपनी तरफ से गारंटी देने के लिए कहा.उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि बिहार के बूथ वर्कर्स परिवारों तक विभिन्न सरकारी योजनाओं के वीडियो दिखाएं और साझा करें.

रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में ब्राजील के उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के साथ बैठक की

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 15 अक्टूबर, 2025 को नई दिल्ली में ब्राजील के उपराष्ट्रपति श्री गेराल्डो अल्कमिन से मुलाकात की। इस बैठक में ब्राजील के रक्षा मंत्री श्री जोस

म्यूसियो मोंटेइरो फिल्हो भी उपस्थित थे।

नेताओं ने वर्तमान में जारी रक्षा संबंधी गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की और रक्षा उपकरणों के सह-विकास एवं सह-उत्पादन के अवसरों की खोज सहित संयुक्त कार्य के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की

दिवाली पर सीएम योगी का डबल गिफ्ट, मुफ्त गैस सिलेंडर और दंगाइयों को कड़ा संदेश

सीएम योगी ने चेतावनी देते हुए कहा, "कोई भी त्यौहार के रंग में भंग डालने का प्रयास करेगा तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी

लखनऊ, .(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहारों के मौसम के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को एक तरफ बड़े तोहफे दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ कानून-व्यवस्था को लेकर कड़े दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने महिलाओं को दिवाली का खास तोहफा दिया और साफ कहा कि शांति भंग करने वालों के लिए जेल के दरवाजे खुले हैं.

मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर की सौगात

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्वला योजना के तहत आने वाले 1.86 करोड़ परिवारों (विशेषकर गरीब और वंचित महिलाओं) को यह

तोहफा दिया गया है. उत्तर प्रदेश सरकार अब साल में दो बार ये सिलेंडर मुफ्त देगी. जिस रसोई गैस के लिए जनता को पैसे देने होते हैं, यूपी सरकार अब साल में ऐसे दो सिलेंडर मुफ्त देगी.

सीएम योगी बोले- अगर किसी को यमराज के दर्शन करने हों तो किसी बेटी को छेड़ने की हिम्मत करें

कड़े दिशा-निर्देश

सीएम योगी ने चेतावनी देते हुए कहा, "कोई भी त्यौहार के रंग में भंग डालने का प्रयास करेगा तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी. कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी." उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे त्यौहार शांति और सौहार्द से मनाएं.

महिलाओं की सेफ्टी पर जोर

महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को सरकार की जिम्मेदारी बताते हुए उन्होंने अपराधियों को सख्त संदेश दिया.

अहमदाबाद में 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को राष्ट्रमंडल संघ द्वारा मंजूरी

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को राष्ट्रमंडल संघ द्वारा मंजूरी दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की

यह भारत को विश्व खेल मानचित्र पर स्थापित करने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के अथक प्रयासों का एक शानदार प्रमाण है

विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे का निर्माण और देशभर में खेल प्रतिभाओं का एक पूल तैयार कर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को एक अद्भुत खेल डेस्टिनेशन बना दिया है

(जीएनएस)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की

मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को राष्ट्रमंडल संघ द्वारा मंजूरी दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है।

प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि आज भारत के लिए अपार हर्ष और गौरव का दिन है। उन्होंने राष्ट्रमंडल संघ द्वारा अहमदाबाद में 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को मंजूरी दिए जाने पर भारत के प्रत्येक नागरिक को हार्दिक बधाई दी। श्री शाह ने कहा कि यह भारत को विश्व खेल मानचित्र पर स्थापित करने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के अथक प्रयासों का एक शानदार प्रमाण है। उन्होंने कहा कि विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे का निर्माण और देशभर में खेल प्रतिभाओं का एक विशाल पूल तैयार कर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को एक अद्भुत खेल डेस्टिनेशन बना दिया है।

रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में शत प्रतिशत की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की

(जीएनएस)।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत पूर्व सैनिकों (ईएसएम) और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में शत प्रतिशत की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह निर्णय सरकार की पूर्व सैनिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता को दशार्ता है। स्वीकृत बढ़ोतरी इस प्रकार हैं:

पेनुरी ग्रांट को प्रति लाभार्थी 4,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इस कदम से 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे वृद्ध और गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों तथा उनकी वीर नारियों को आजीवन आर्थिक सुरक्षा व निरंतर सहायता सुनिश्चित होगी, जिनकी कोई नियमित आय नहीं है। इसके अलावा, दो आश्रित बच्चों (कक्षा 1 से स्नातक तक) या दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रही वीर नारियों के लिए शिक्षा अनुदान को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति कर दिया गया है, जिससे शिक्षा के अवसरों को और सशक्त सहयोग मिलेगा।

विवाह अनुदान को प्रति लाभार्थी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। यह संशोधित अनुदान पूर्व सैनिकों की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह और वीर नारियों के पुनर्विवाह पर लागू होगा, बशर्ते ये विवाह इस आदेश के जारी होने के बाद संपन्न हुए हों।

संशोधित दरें 1 नवंबर, 2025 से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर लागू होंगी। इन संशोधनों से सरकार पर लगभग 257 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय भार आएगा, जिसे सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) से वहन किया जाएगा।

इन योजनाओं का वित्तपोषण रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष के माध्यम से किया जाता है, जो एएफएफडीएफ का एक उपकोष है और पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों के कल्याण के लिए समर्पित है।

यह निर्णय गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और निम्न आय वर्ग के आश्रितों के लिए सामाजिक सुरक्षा के ताने-बाने को सशक्त बनाता है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की लायंस क्लब के अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ गांधीनगर में बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छता से सेमीकंडक्टर तक सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सकारात्मक नेतृत्व के फलस्वरूप भारत की ग्लोबल इमेज में वृद्धि हुई है
- प्रधानमंत्री की 'वसुधैव कुटुम्बकम्' तथा 'सबका साथ-सबका विकास' की राजनीति से विश्व के देशों में भारत के प्रति विश्वास दृढ़ हुआ है

गांधीनगर, 15 अक्टूबर : लायंस क्लब इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों ने बुधवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से भेंट की।

मुख्यमंत्री ने अपनी अध्यक्षता में आयोजित इस मुलाकात-बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छता से लेकर सेमीकंडक्टर तक सभी क्षेत्रों के

विकास को प्राथमिकता दी है। इसके फलस्वरूप देश विकास के नित-नए शिखर पार कर रहा है।

श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सकारात्मक नेतृत्व के परिणामस्वरूप भारत की ग्लोबल इमेज में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' तथा 'सबका साथ-सबका विकास' की जो राजनीति दी है, उससे विश्व के देशों में भारत के प्रति विश्वास बढ़ा है।

मुख्यमंत्री ने लायंस क्लब की विश्वभर के देशों में सेवाभावी संस्था के रूप में उपस्थिति की प्रशंसा की और संस्था को उसके विकासोन्मुखी कार्यों में राज्य सरकार के उचित सहयोग का भी आश्वासन दिया।

उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू कराए गए अभियानों से आ रहे परिवर्तनों की भूमिका दी और लायंस क्लब द्वारा सरकार के अभियानों में सक्रिय भागीदारी की भी सराहना की।

मद्यनिषेद्य विभाग, उ0प्र0 द्वारा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में नशा मुक्त भारत अभियान, राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन सम्पन्न

मद्यनिषेद्य विभाग, उ0प्र0 द्वारा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में नशा मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत दिनांकः 15 अक्टूबर 2025 को आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार / विशेष कार्यक्रमों का विवरण-

वाईकेके

दिनांकः 15 अक्टूबर 2025 को नशा मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत शताब्दी प्रेक्षागृह, कृषि विज्ञान संस्थान, बी०एच०यू० में मद्यनिषेध विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा छात्र अधिष्ठाता, छात्र कल्याण संकाय, बी०एच०यू के सहयोग से नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरुकता हेतु मद्यनिषेध प्रदर्शनी, संगोष्ठी सहित विभिन्न प्रकार के शिक्षात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रुप में श्री नितिन अग्रवाल, माननीय मंत्री आबकारी एवं मद्यनिषेध विभाग, उ०प्र० की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय कुलपति महोदय प्रो0 अजीत कुमार चतुवेर्दी द्वारा की गयी।

सर्वप्रथम माननीय मंत्री आबकारी एवं मद्यनिषेध विभाग, उ०प्र० एवं अन्य

गणमान्य अतिथियों द्वारा मद्यनिषेध प्रदर्शनी का उदघाटन एवं अवलोकन किया गया तदोपरान्त मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यापर्ण कर माननीय मंत्री जी के करकमलों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन करते हुए कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। श्री आर0एल0 राजवंशी, राज्य मद्यनिषेध अधिकारी उङ्गप्रङ्ग द्वारा परिचयात्मक उदबोधन में विभाग की उपलब्धियों के साथ ही नशा मुक्त भारत अभियान के संदर्भ में अवगत कराया गया।

माननीय मंत्री श्री नितिन अग्रवाल, आबकारी एवं मद्यनिषेध विभाग, उङ्गप्रङ्ग द्वारा प्रदेश के युवाओं में नशे की बढती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए जनमानस से अपील की गयी नशा मुक्त भारत अभियान व एक युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम को गति प्रदान करने की आवश्यकता है। इस कार्य में शासकीय प्रयासों के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत विजन 2047 के नशा मुक्त भारत अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु पूर्ण मनोयोग से योगदान देने हेतु प्रेरित किया। प्रो० अजीत कुमार चतुवेर्दी, कुलपति काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा मादक पदार्थों के दुरुपयोग रोकथाम व जनजागरुकता हेतु युवाओं की सहभागिता के संबंध में प्रकाश डाला गया। प्रो० अनुपम कुमार नेमा, छात्र अधिष्ठाता, छात्र कल्याण संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा मादक पदार्थों के दुरुपयोग, कारण व समाधान पर बहुआयामी दृष्टिकोण से चर्चा किया गया।

सम्पादकीय

भारत-अफगानिस्तान के ऐतिहासिक संबंधों को नई ताजगी

भारत-अफगानिस्तान संबंधों की ऐतिहासिक जड़ें बहुत गहरी हैं] अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्तकी की भारत यात्रा ने पुरानी दोस्ती को नई जान पूंक दी है। मुत्तकी बीते गुरुवार को राजधानी दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से विस्तृत चर्चा की। यह 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान के किसी वरिष्ठ नेता की पहली भारत यात्रा है। इस मुलाकात में भारत ने काबुल में अपने पूर्ण दूतावास को फिर से सयि करने की घोषणा की, जो चार वर्षो के अंतराल के बाद एक बड़ा वूटनीतिक कदम है। मुत्तकी की यात्रा से एक उम्मीद बंधी है। विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान को 'साझा खतरा' बताया, जबकि तालिबान ने 2025 के पहलगाम हमले की निदा की। भारत-अफगानिस्तान संबंध शताब्दियों की परीक्षा से गुजरे हैं। प्राचीन बौद्ध विरासत से आधुनिक बुनियादी ढांचे तक, ये बंधन लचीले साबित हुए। मुत्तकी की यात्रा मानवतावादी सहायता को वूटनीतिक संवाद में बदलने का अवसर है। जैसे अशोक के शिलालेख आज भी बोलते हैं। दोनों देशों को आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास जैसे साझा मुद्दों पर एकजुट होना होगा। यह न केवल क्षेत्रीय शांति के लिए जरूरी है, बल्कि साझा इतिहास की मांग भी। लेकिन मुत्तकी की यह यात्रा केवल वर्तमान की राजनीति नहीं, बल्कि भारत-अफगानिस्तान के गहन ऐतिहासिक बंधनों की याद दिलाती है। सिधु घाटी सयता से लेकर आधुनिक विकास परियोजनाओं तक, ये संबंध सांस्वृतिक, आर्थिक और रणनीतिक धागों से बुने गए हैं। भारत और अफगानिस्तान के संबंध प्राचीन काल से ही गहरे हैं, जब ये क्षेत्र एक सांस्वृतिक निरंतरता का हिस्सा थे। सिधु घाटी सयता (लगभग 3300- 1300 ईंसा पूर्व) के अवशेष अफगानिस्तान के उत्तरी भागों में भी मिलते हैं, जो व्यापारिक मार्गो के माध्यम से जुड़े हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय (305 ईंसा पूर्व) यह संबंध औपचारिक रूप ले चुके थे। सेल्यूकस निकेटर ने अफगान क्षेत्र मौर्य साम्राज्य को सौंप दिया, बदले में 500 हाथी और वैवाहिक संबंध प्राप्त किए। सम्राट अशोक (268-232 ईंसा पूर्व) ने अफगानिस्तान को बौद्ध धर्म का वेंद्र बनाया। वंधार में उनके शिलालेख आज भी मौजूद हैं, जो धम्म के प्रचार की गवाही देते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भी, इंडो-ग्रीक और वुशान साम्राज्यों ने इस क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप से जोड़े रखा। वुषाण शासक कनिष्क (मध्य पहली शताब्दी) ने बौद्ध धर्म को पुनजावित किया, जिसका प्रभाव गंधार कला में दिखता है। ये प्राचीन संबंध केवल राजनीतिक नहीं, सांस्वृतिक थे। अफगानिस्तान के बामियान बुद्ध (जो 2001 में तालिबान द्वारा नष्ट किए गए) भारतीय बौद्ध विरासत के प्रतीक थे। व्यापार मार्गो ने मसाले, रत्न और विचारों का आदान-प्रदान सुनिाित किया, जो आज भी दोनों देशों की साझा विरासत को दशार्ता है। मध्यकाल में अफगानिस्तान भारत के लिए अवसर और चुनौती दोनों रहा। 10वीं शताब्दी से गजनवी, गौरी, खिलजी, लोदी और मुगल जैसे अफगान मूल के वंशों ने उत्तरी भारत पर आामण किए, जो राजनीतिक उथल-पुथल लाए लेकिन सांस्वृतिक समन्वय भी। महमूद गजनवी (998- 1030) के आव्रमणों ने सोमनाथ मंदिर को लूटा, लेकिन इन्होंने फारसी साहित्य और वास्तुकला को भारत में रोपा। गौरी वंश (12वीं शताब्दी) ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, जो अफगान शासकों द्वारा संचालित थी। मुगल काल (1526-1858) में यह संबंध और गहरा हुआ। बाबर, अफगान मूल का था। 18वीं शताब्दी में अहमद शाह दुरानी ने अफगान साम्राज्य स्थापित किया, जिसने पंजाब तक विस्तार किया, लेकिन महाराजा रणजीत सिह के सिख साम्राज्य ने इसे रोका। इस काल में आर्थिक लेन-देन फला-पूला। अफगानिस्तान के सूखे मेवे, घोड़े और ऊनी वस्त्र भारत पहुंचे, जबकि भारतीय वस्त्र और मसाले अफगान बाजारों में बिके। सांस्वृतिक रूप से, सूफी संतों जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती (अजमेर) ने दोनों क्षेत्रों को जोड़ा। हालांकि आव्रमणों ने तनाव पैदा किया, लेकिन ये संबंध विनाशकारी नहीं, बल्कि परिवर्तनकारी साबित हुए।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में दो दिवसीय 'नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव' तथा 'मेयरल समिट' का शुभारंभ कराया

प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में देश में सर्वप्रथम 'शहरी विकास वर्ष' जैसे कॉन्सेप्ट शुरू किए और लोगों का 'ईज ऑफ लिविंग' सुनिश्चित किया : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- कॉन्क्लेव में सरदार पटेल की शहरी विकास की तत्कालीन विचारधारा को आधुनिक विकास के साथ जोड़ने पर होगा चिंतन-मंथन
- 100 वर्ष पहले सरदार पटेल ने अपनी प्रशासनिक कुशलता से सुव्यवस्थित अर्बन प्लानिंग द्वारा आदर्श शहर का निर्माण करके देश को सिटीजन-सेंट्रिक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का अनूठा मॉडल दिया
- प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अहमदाबाद ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के साथ-साथ वर्ल्ड क्लास सिटी की श्रेणी में भी गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया
- साबरमती रिवरफ्रंट समग्र भारत के लिए अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का एक आदर्श मॉडल बना

भारत के विभिन्न शहरों के मेयर, कमिशनर तथा प्रतिनिधि कॉन्क्लेव में उपस्थित रहे

गांधीनगर, 15 अक्टूबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को अहमदाबाद में दो दिवसीय 'नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव' तथा 'मेयरल समिट' का शुभारंभ कराया। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में केन्द्र सरकार तथा अहमदाबाद महानगर पालिका द्वारा इस कॉन्क्लेव एवं समिट का आयोजन किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर कहा कि सार्वजनिक जीवन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल के 24 पूर्ण होने के अवसर पर राज्यभर में विकास सप्ताह मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सबसे पहली बार राजनीति में 'विकास' शब्द को सक्रिय रूप से व्यापक बनाया है।

श्री पटेल ने कहा कि यह कॉन्क्लेव एवं समिट अहमदाबाद के लिए विशेष है, कारण कि आज समग्र देश प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। ऐसे में इस कॉन्क्लेव में इस विषय पर चिंतन-मंथन किया जाएगा कि सरदार पटेल की शहरी विकास की तत्कालीन विचारधारा को आधुनिक विकास के साथ कैसे जोड़ा जाए।

अहमदाबाद के विकास में सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान के ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार साहब ने 1924 से 1928 के दौरान तत्कालीन अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी की शुरूआत की थी। सरदार साहब ने लगभग 100 वर्ष पहले अपनी प्रशासनिक कुशलता तथा सुव्यवस्थित अर्बन प्लानिंग द्वारा आदर्श शहर का निर्माण कर देश को सिटीजन-सेंट्रिक लोकल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का अनूठा मॉडल दिया था।

श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल से लेकर देश के प्रधानमंत्री के रूप में सरदार पटेल के इन्हीं विचारों से प्रेरित रहते हुए देश में शहरी विकास में परिवर्तन से नई क्रांति लाए हैं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अहमदाबाद शहर ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के साथ-साथ वर्ल्ड क्लास सिटी की श्रेणी में भी गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है।

उन्होंने आगे कहा कि अहमदाबाद का विश्व प्रसिद्ध साबरमती रिवरफ्रंट देश के अन्य शहरों के लिए अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का आदर्श मॉडल बना है। इसके अतिरिक्त; श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में देश में सबसे पहली बार 'शहरी विकास वर्ष' का जो कॉन्सेप्ट दिया, वह लोगों के 'ईज ऑफ लिविंग' को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। मुख्यमंत्री ने जोड़ा कि हम उन्हीं के विचारों से प्रेरणा लेकर 2025 को 'शहरी विकास वर्ष' के रूप में मना रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने अर्बन मोबिलिटी के बारे में कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी देश के ऐसे प्रथम मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने शहरों के लिए सफल बीआरटीएस जनमार्ग मॉडल का विचार दिया। आज मेट्रो तथा हाईस्पीड रेल परियोजनाओं के माध्यम से मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट में अहमदाबाद अर्बन मोबिलिटी के लिए एक आदर्श बन रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि पिछले दो दशक में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में शहरीकरण का स्तर बहुत बढ़ा है और अमृत 2.0 एवं स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जैसे प्रोजेक्ट्स द्वारा शहरी ढाँचे को परिवर्तित करने का कार्य हो रहा है।

उन्होंने कहा कि यह कॉन्क्लेव प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारे शहरों को विकसित भारत@2047 के अनुरूप बनाने, इनोवेशन को प्रोत्साहन देने तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा तय करने का एक सशक्त मंच बनेगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री ने विकसित भारत@2047 के लिए जो संकल्प किया है, उसे पूरा करने में यह समिट हमारे सामूहिक उद्देश्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी।

उन्होंने सभी से 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र के साथ स्वदेशी को प्राथमिकता देकर प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने का माध्यम बनने का भी अनुरोध किया।

इस अवसर पर अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभाबेन जैन ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में अहमदाबाद में 'नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव' तथा 'मेयरल समिट' का आयोजन हो रहा है। यह सबके लिए गौरव एवं सम्मान की बात है। श्रीमती जैन ने जोड़ा कि अहमदाबाद शहर ने शहरी विकास के क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियाँ हासिल की हैं। इतना ही नहीं; विरासत की परंपरा भी अहमदाबाद ने बनाए रखी है और साथ ही कूड़े से ऊर्जा एवं ऊर्जा से अवसर का संकल्प भी अहमदाबाद ने किया है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के दूरदर्शी नेतृत्व में अहमदाबाद शहर ने साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट, मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन (बीआरटीएस, एएमटीएस, मेट्रो), स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, शहरी हरियाली, सांस्कृतिक एवं खेल-कूद की ढाँचागत सुविधाओं और विश्व स्तरीय नागरिक सुविधाओं जैसी माइलस्टोन समान पहलें की हैं। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं; इस समिट के माध्यम से भारत के शहरी परिदृश्य को एक करने, नवीनता लाने, नेतृत्व करने तथा परिवर्तन लाने के लिए लीडर्स को एक साथ लाने का प्रयास है।

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की अपर सचिव श्री डी. तारा ने इस कॉन्क्लेव में अपने संबोधन में कहा कि आगामी समय में सस्टेनेबल शहरी विकास के लिए नागरिकों को भी अपना सक्रिय योगदान देगा। हमारे शहरों की कूड़ा, ट्रैफिक, ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियाँ आदि समस्याओं के निवारण के लिए हम सभी को साथ मिलकर कार्य करना होगा। एक नागरिक के रूप में हमें यह सोचना चाहिए कि किस प्रकार हम छोटे-छोटे कदम उठाकर अपने घर से ही शहरी विकास में योगदान दें। हमें कूड़े की उचित निकासी, पानी की बचत, वृक्षारोपण, यातायात नियमों का पालन जैसे कर्तव्य जागरूकता के साथ निभाने होंगे।

उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के अहमदाबाद नगरीय विकास प्राधिकरण (औडा) के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल में शहर के विकास के लिए मंजूर किए गए मास्टर प्लान का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मास्टर प्लान एवं अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के कारण आज अहमदाबाद में 10 प्रतिशत से अधिक स्लम क्षेत्र नहीं रहा है। उन्होंने आगामी समय में अर्बन रेजीलिएंट टाउन प्लानिंग की जरूरत पर भी बल दिया।

इस अवसर पर साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआरएफडीसीएल) के अध्यक्ष श्री आई. पी. गौतम ने अपने विचार व अनुभव व्यक्त करते हुए कहा कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शहरी विकास को बहुत महत्व दिया, जिसके कारण आज गुजरात के सभी शहरों का विकास हो रहा है।

श्री गौतम ने जोड़ा कि श्री नरेन्द्र मोदी की शहरी विकास आधारित नीतियों के कारण आज गुजरात सहित अहमदाबाद को बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिले हैं, जिनकी आज केवल भारत देश में ही नहीं, अपितु समग्र विश्व में प्रशंसा हो रही है।

अहमदाबाद मनपा आयुक्त श्री बंछानिधि पाणि ने स्वागत संबोधन में देश के विभिन्न राज्यों से पधारे मेयर्स, शहरी विकास विभाग के पदाधिकारियों सहित सभी का स्वागत किया।

बीएसएनएल ने दिवाली पर एक महीने के लिए मुफ्त मोबाइल सेवाओं का ऑफर दिया

आईएमएफ द्वारा भारत के विकास अनुमान को बढ़ाना देश के आर्थिक लचीलेपन और मजबूत बुनियादी कारकों का प्रमाण: श्री गोयल

रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग में प्रौद्योगिकी और नवोन्मेषण के विकास में अग्रणी बनने की क्षमता, इससे भारत का वैश्विक नेतृत्व सुदृढ़ होगा: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल

(जीएनएस)।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज सीआईआई द्वारा आयोजित 7वें भारतीय रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स सम्मेलन में मुख्य भाषण देते हुए कहा कि रसायन एवं पेट्रोकेमिकल उद्योग में नई प्रौद्योगिकियों के विकास में अग्रणी बनने तथा अर्थव्यवस्था एवं उद्योग के लिए अत्याधुनिक समाधान उपलब्ध कराने में भारत को अग्रणी बनाने की क्षमता है।

श्री गोयल ने रेखांकित किया कि सरकार की नीतियों का उद्देश्य संतुलित विकास सुनिश्चित करना है जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ हो, घरेलू अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो और भारत वैश्विक मंच पर प्रमुखता से स्थापित हो। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा हाल ही में 2025 के लिए भारत के विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.6 प्रतिशत करने का उल्लेख किया, जो इसके पूर्व के 6.4 प्रतिशत के अनुमान से अधिक है। यह देश की आर्थिक दृढ़ता और मजबूत बुनियादी कारकों का प्रमाण है।

श्री गोयल ने इस बात पर बल दिया कि महान और उन्नत राष्ट्र प्रौद्योगिकी और नवोन्मेषण पर ध्यान केंद्रित करके अपनी स्थिति प्राप्त करते हैं और भारत को अपने विकास लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए इसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए।

श्री गोयल ने जोर देकर कहा कि तेल-समृद्ध देश भी मूल्यवर्धित उत्पादों, स्वच्छ ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन-संबंधी प्रौद्योगिकियों में निवेश कर रहे हैं, जो नवोन्मेषण-केंद्रित विकास की ओर वैश्विक बदलाव को दशार्ता है। उन्होंने कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन से निपटने और प्रौद्योगिकीय रूप से आगे बढ़ने की

आवश्यकता निरंतर बनी हुई है। उन्होंने विज्ञान, अनुसंधान एवं विकास तथा नवोन्मेषण के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ये भारत के एक उन्नत राष्ट्र बनने और 2047 तक विकसित भारत के विजन को अर्जित करने की यात्रा की रीढ़ हैं।

श्री गोयल ने रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्र की महत्वपूर्ण क्षमता और राष्ट्र के समग्र विकास में इसकी कार्यनीतिक भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस सेक्टर का कृषि, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा, निर्माण, ऊर्जा और गतिशीलता सहित कई उद्योगों में व्यापक उपयोग और प्रभाव है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस क्षेत्र के उत्पाद और सेवाएं सर्वव्यापी हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विनिर्माण और उपभोग इको-सिस्टम के लगभग हर पहलू को प्रभावित करती हैं। श्री गोयल ने उद्योग जगत के अग्रणी व्यक्तियों से अपनी क्षमताओं का सावधानीपूर्वक आकलन करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने का आग्रह किया जहां भारत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त कर सकता है। उन्होंने इस सेक्टर के लिए वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाकर और वर्तमान मामूली योगदान से आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नेतृत्व का लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। श्री गोयल ने आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन और विविधीकरण के महत्वपूर्ण महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि किसी एक आपूर्तिकर्ता या सीमित संख्या में देशों पर निर्भरता कमजोरियां पैदा कर सकती है। उन्होंने बताया कि जहां कुछ उत्पादों को आत्मनिर्भरता और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए घरेलू संरक्षण की आवश्यकता हो सकती है, वहीं दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता और सतत विकास प्राप्त करने के लिए इस सेक्टर को वैश्विक बाजारों के साथ समेकित रहना होगा।

श्री गोयल ने वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण के लिए भारत के कार्यनीतिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला, साथ ही यह सुनिश्चित किया कि घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धी बने रहें। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को एक उन्नत अर्थव्यवस्था बनने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना, व्यापार के अवसरों का पता लगाना और निवेश आकर्षित करना आवश्यक है, साथ ही वैश्विक एकीकरण और घरेलू उद्योग संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। श्री गोयल ने मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत करने और भारत के वैश्विक व्यापार क्षेत्र का विस्तार करने पर सरकार के निरंतर ध्यान को रेखांकित किया। उन्होंने मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन सहित कई देशों और क्षेत्रों के साथ हुए समझौतों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने बताया कि ये व्यापारिक समझौते भारतीय उत्पादों के लिए बाजार खोलने, प्रौद्योगिकी और निवेश को आकर्षित करने और नवोन्मेषण-केंद्रित सेक्टरों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि घरेलू उद्योगों को अनुचित जोखिम का सामना न करना पड़े। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का उद्देश्य एक बेहतर संतुलन बनाना है, जिसमें भारतीय व्यवसायों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाना, निर्यात को बढ़ावा देना तो है ही, साथ ही घरेलू उत्पादन की रक्षा करना और 140 करोड़ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना भी है। श्री गोयल ने कहा कि यद्यपि सरकार वैश्विक एकीकरण चाहती है, फिर भी वह बाजार की गतिशीलता, आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन तथा निष्पक्ष एवं टिकाऊ व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करने के प्रति सजग है, जिससे उद्योग और अंतिम उपभोक्ता दोनों को लाभ हो।

श्री गोयल ने उद्योग जगत के प्रतिभागियों से सहयोगात्मक रूप से

निर्वाचन आयोग ने दिव्यांगजनों के लिए मतदान को आसान बनाने हेतु निर्देश जारी किए

(जीएनएस)।

निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर, 2025 को बिहार विधान सभा के आम चुनाव और 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि चुनाव दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए सुलभ हों।

बिहार में, सभी मतदान केंद्र भूतल/सड़क प्रवेश स्तर पर स्थित होंगे और दिव्यांग मतदाताओं और व्हीलचेयर वाले वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए उचित ढलान वाले रैंप होंगे। यह निर्देश भी दिया गया है कि दिव्यांग मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों को मतदान केंद्रों में प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जाए।

आयोग ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सुविधा के लिए नियमित मतदाता सूचना पर्चियों (वीआईएस) के साथ-

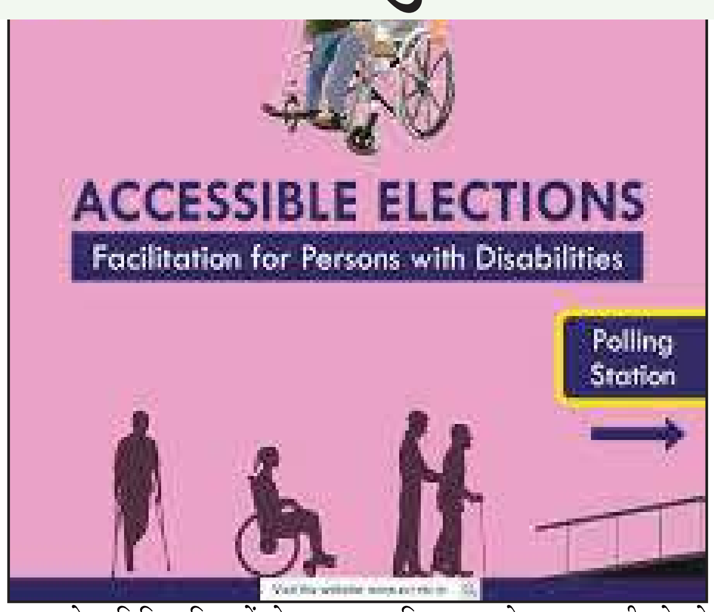

साथ ब्रेल लिपि सुविधाओं के साथ सुगम्य मतदाता सूचना पर्चियां जारी करने का निर्देश दिया है।

निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 49एन के अनुसार, दृष्टिबाधित व्यक्ति मतदान केन्द्र पर अपनी ओर से वोट डालने के लिए अपने साथ एक सहयोगी को ले जा सकते हैं।

सभी मतदान केंद्रों पर ब्रेल लिपि में डमी बैलेट शीट भी उपलब्ध कराई जाएंगी। कोई भी दृष्टिबाधित मतदाता बिना किसी सहयोगी की मदद के ईवीएम की बैलेट यूनिट पर ब्रेल लिपि सुविधा का उपयोग करके स्वयं इस शीट का उपयोग करके अपना वोट डाल सकता है।

आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान के दिन मतदान केंद्र पर दिव्यांगजनों के लिए उचित परिवहन सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। दिव्यांग मतदाता ईसीआईएनईटी के दिव्यांग (सक्षम) मॉड्यूल पर पंजीकरण कराकर परिवहन और व्हीलचेयर सुविधा का अनुरोध भी कर सकते हैं।

ये सुविधाएं बिहार के 90 हजार 712 मतदान केंद्रों में से प्रत्येक पर उपलब्ध होंगी। एक अन्य पहल के अंतर्गत 292 मतदान केंद्रों का प्रबंधन विशेष रूप से दिव्यांगजनों द्वारा किया जाएगा।

आगामी बिहार चुनावों में धनबल के इस्तेमाल को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश जारी किए

चुनाव व्यय पर निगरानी रखने के लिए व्यय पर्यवेक्षक तैनात किए गए

(जीएनएस)।

भारत निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर, 2025 को बिहार विधान सभा के आम चुनाव और 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की।

आगामी चुनावों में धनबल, मुफ्तखोरी के साथ-साथ ड्रग्स, नशीले पदार्थों और शराब के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए, आयोग ने राज्य पुलिस विभाग, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग, आयकर विभाग, एफआईयू-आईएनडी, आरबीआई, एसएलबीसी, डीआरआई, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीमा शुल्क, ईडी, एनसीबी, आरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, बीसीएएस, एएआई, डाक विभाग, राज्य वन विभाग और राज्य सहकारिता विभाग सहित सभी प्रवर्तन

एजेंसियों को निर्देश जारी किए हैं।

उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले चुनावी खर्च की निगरानी रखने के लिए व्यय पर्यवेक्षकों को पहले ही तैनात कर दिया गया है और वे चुनाव की अधिसूचना जारी होने के दिन ही अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं। इस दौरान वे व्यय निगरानी में लगी सभी टीमों से मिलेंगे।

मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन-बल या अन्य प्रलोभन के किसी भी संदिग्ध मामले पर नजर रखने के लिए उड़न दस्ते, निगरानी दल, वीडियो निगरानी दल चौबीसों घंटे सतर्क रहेंगे।

आयोग ने चुनाव अवधि के दौरान वास्तविक समय के आधार पर एफ.एस, एस.एस.टी. और प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किए गए अवरोधन/जब्ती की रिपोर्टिंग के लिए चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली (ई.एस.एम.एस.) नामक ऑनलाइन प्रणाली को भी सक्रिय किया है।

6 अक्टूबर, 2025 को चुनावों की घोषणा के बाद से, विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कुल 33.97 करोड़ रुपये मूल्य की नकदी, शराब, ड्रग्स और निःशुल्क उपहार जब्त किए गए हैं।

आयोग ने इस बात पर भी बल दिया कि प्रवर्तन प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन निर्देशों के प्रवर्तन के लिए जांच और निरीक्षण के दौरान आम नागरिकों को असुविधा या परेशानी न हो।

कोई भी आम नागरिक सी-विजिल ऐप के माध्यम से ऐसे किसी भी उल्लंघन के संबंध में शिकायत कर सकता है।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR

वडोदरा मंडल द्वारा त्योहारी सीजन 2025 के लिए व्यापक भीड़ प्रबंधन व्यवस्था लागू

यात्रियों की बढ़ती संख या के मद्देनजर सुरक्षित और व्यवस्थित त्योहारी यात्रा सुनिश्चित करने हेतु वड़ोदरा मंडल की सक्रिय तैयारी

आगामी त्योहारों के दौरान होने वाली भीड़ और यात्रियों की आवाजाही में अपेक्षित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम रेलवे के वड़ोदरा मंडल द्वारा सुरक्षित, सुचारू और कुशल रेल संचालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक भीड़ प्रबंधन और यात्री सुविधा उपाय शुरू किए गए हैं। वडोदरा एवं प्रतापनगर स्टेशनों अंतर्गत विशेष व्यवस्था की गई है।

श्री अनुभव सक्सेना, जनसंपर्क अधिकारी, वडोदरा मंडल द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वडोदरा स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए एक निर्दिष्ट यात्री होल्डिंग क्षेत्र बनाया गया है, जिसमें यात्रिओं के लिए बैठने की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल सुविधा, पर्याप्त रोशनी, पंखे और सार्वजनिक घोषणा प्रणाली जैसी आवश्यक यात्री सुविधाएं प्रदान की गयी है।

वडोदरा और प्रतापनगर स्टेशनों पर यात्री प्रवेश और टिकट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त बुकिंग काउंटर चालू किए गए हैं। प्रत्येक स्टेशन पर कतार नियमन,

यात्री सहायता और उनकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त टिकट जांच कर्मचारियों और आरपीएफ कर्मियों की तैनाती भी की गयी है।

श्री सक्सेना ने आगे बताया कि ट्रेन के प्रस्थान से पहले प्रतीक्षारत यात्रियों को आराम से बैठाने के लिए वडोदरा स्टेशन पर पर्याप्त कवर्ड होल्डिंग क्षमता बनाई गई है। समर्पित होल्डिंग एरिया के रूप में प्लेटफार्म संख्या 6 के निकट 300 वर्ग मीटर से अधिक के सुरक्षित स्थान की व्यवस्था की गई है।

रेलवे सुरक्षा बल (फ्द्धऋ) के जवान प्रभावी समन्वय बनाए रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ड्यूटी के दौरान निर्बाध डिजिटल संचार के लिए वॉकी-टॉकी और बॉडी वॉर्न कैमरा का उपयोग कर रहें हैं। फ्द्धऋ द्वारा सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी तथा यात्रियों की आवाजाही पर चौबीसों घंटे निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, वास्तविक समय पर समन्वय और किसी भी स्थिति पर त्वरित प्रतिक्रिया की सुविधा के लिए प्रभागीय नियंत्रण कार्यालय में एक समर्पित युद्ध कक्ष स्थापित किया गया है।

पश्चिमी रेलवे का वडोदरा डिवीजन यात्रियों से अपील करता है कि वे प्लेटफॉर्म या प्रवेश द्वार के पास भीड़ लगाने के बजाय निर्धारित होल्डिंग एरिया का उपयोग करें, ताकि व्यस्त समय के दौरान आवाजाही को सुचारू रूप से नियंत्रित किया जा सके। यात्रियों से यह भी आग्रह किया जाता है कि वे ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के दिशानिर्देशों का पालन करें, क्योंकि ये व्यवस्थाएं सभी यात्रियों की सुरक्षा, आराम और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए की गई हैं।

अहमदाबाद मंडल के आंबलियासन-विजापुर रेलखंड का गेज परिवर्तन कार्य पूर्ण

42.32 किमी लंबा खंड अब ब्रॉड गेज में परिवर्तित, 16 एवं 17 अक्टूबर 2025 को होगा संरक्षा निरीक्षण

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के आंबलियासन-विजापुर रेलखंड (42.32 किमी) का गेज परिवर्तन कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अब यह खंड मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तित होकर यात्रियों के लिए आधुनिक और सुरक्षित परिचालन के लिए तैयार है। इस खंड का संरक्षा निरीक्षण रेल संरक्षा आयुक्त (CRS), पश्चिम रेलवे द्वारा 16 एवं 17 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा, जिसमें 16 एवं 17 अक्टूबर को मोटर ट्रॉली निरीक्षण तथा 17 अक्टूबर को इंजन स्पीड ट्रायल 120 किमी/घंटा की गति से किया जाएगा।

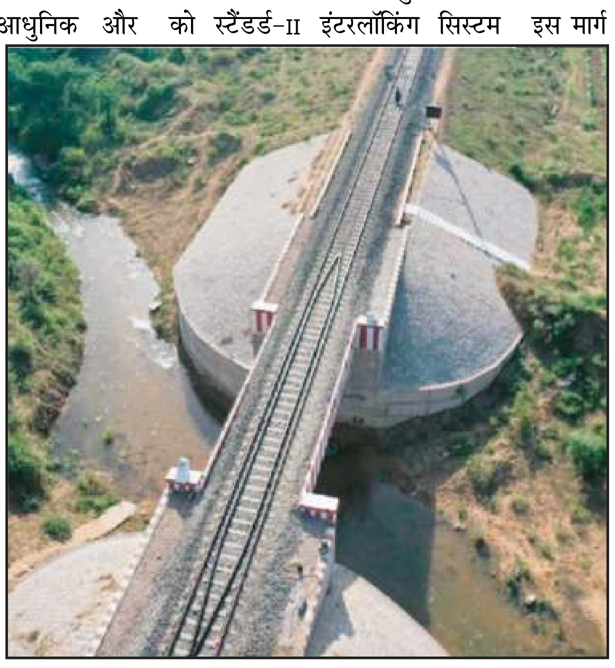

इस परियोजना को वर्ष 2022-23 में स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यह परियोजना को 16 मई 2022 को ₹415.37 करोड़ की अनुमानित लागत से मंजूरी दी गई थी। इस खंड में 02 मेजर ब्रिज, 51 माइनर ब्रिज और 45 नए रोड अंडर ब्रिज (RUBs) का निर्माण किया गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे लाइन को लेवल क्रॉसिंग के समीप फेंसिंग द्वारा सुरक्षित किया गया है और इस मार्ग पर कुल 04 लेवल क्रॉसिंग्स हैं।

इस ब्रॉड गेज लाइन में 60 किग्रा के नए रेल पैनल बिछाए गए हैं। आंबलियासन और विजापुर स्टेशनों को स्टैंडर्ड-II इंटरलॉकिंग सिस्टम और मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग (MACLS) के साथ आधुनिक सुरक्षा उपायों से सुसज्जित किया गया है, जिससे ट्रेनों के संचालन की सुरक्षा और दक्षता में उल्लेखनीय सुधार होगा। इस नए ब्रॉड गेज के माध्यम से यात्रियों को अब देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों और बड़े शहरों से प्रत्यक्ष कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे यात्रा अधिक सुविधाजनक, तेज और सुगम होगी।

इस गेज परिवर्तन परियोजना से यात्रियों को अब तेज, सुरक्षित और आरामदायक रेल यात्रा उपलब्ध होगी। इस मार्ग से उत्तरी गुजरात के ग्रामीण एवं औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर रेल कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी, जिससे यात्रियों का यात्रा समय कम होगा और सुविधा में सुधार होगा। साथ ही, क्षेत्रीय व्यापार और कृषि को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस परियोजना के निर्माण और संचालन के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और समग्र क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास भी होगा। नए ब्रॉड गेज कनेक्शन से भविष्य में नई यात्री और मालगाड़ियों के परिचालन की संभावनाएँ भी बढ़ेंगी।

पश्चिम रेलवे की यह परियोजना यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। संरक्षा निरीक्षण के पूर्ण होने के बाद जल्द ही इस मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ किया जाएगा, जिससे यात्रियों को आधुनिक, तेज और सुरक्षित रेल यात्रा का लाभ मिलेगा।

पश्चिम रेलवे वलसाड एवं हिसार के बीच चलाएगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

मुंबई,

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा दिवाली एवं छठ पूजा के त योहारी सीजन के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से वलसाड एवं हिसार स्टेशनों के बीच विशेष किराए पर एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार है:

1. ट्रेन संख्या 04728/04727 वलसाड-हिसार साप्ताहिक स्पेशल [08 फेरे]

ट्रेन संख्या 04728 वलसाड-हिसार स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को वलसाड से 14:50 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 14:05 बजे हिसार पहुँचेगी। यह ट्रेन 16 अक्टूबर से 06 नवंबर, 2025 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04727 हिसार-वलसाड स्पेशल प्रत्येक बुधवार को हिसार से 12:05 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 11.30 बजे वलसाड पहुँचेगी। यह ट्रेन 15 अक्टूबर से 05 नवंबर 2025 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में नवसारी, सूरत, भरूच, वडोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बिजयनगर, नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, रींगस, नीम का थाना, नारनौल, रेवाड़ी, चरखी दादरी, भिवानी और हांसी स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 04728 की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू है। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे चलायेगी साबरमती-गोरखपुर और साबरमती-बेगूसराय के बीच अनारक्षित फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें

पश्चिम रेलवे द्वारा आगामी दिवाली और छठ पूजा त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए साबरमती-गोरखपुर और साबरमती-बेगूसराय के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें विशेष किराये पर चलाने का निर्णय लिया गया है। इन स्पेशल ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

- ट्रेन संख्या 09429/09430 साबरमती-गोरखपुर त्रि-साप्ताहिक अनारक्षित स्पेशल ट्रेन विशेष किराए पर (12 फेरे)

ट्रेन संख्या 09429 साबरमती-गोरखपुर त्रि-साप्ताहिक अनारक्षित स्पेशल साबरमती से 16 अक्टूबर 2025 से 26 अक्टूबर 2025 तक प्रति गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को सुबह 08:50 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन सुबह 10:00 बजे गोरखपुर पहुचेंगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 09430 गोरखपुर-साबरमती त्रि-साप्ताहिक अनारक्षित स्पेशल गोरखपुर से 17 अक्टूबर 2025 से 27 अक्टूबर 2025 तक प्रति शुक्रवार, शनिवार और सोमवार को दोपहर 13:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन दोपहर 15:30 बजे साबरमती पहुचेंगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन महेसाणा, पालनपुर, आबूरोड, मारवाड़ जं., अजमेर, जयपुर, गांधी नगर जयपुर, दौसा, बाँदीकुई जं., भरतपुर, ईदगाह आगरा, टुंडला, इटावा, गोविंदपुरी,उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, मनकापुर एवं बस्ती स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में सभी अनारक्षित श्रेणी के कोच रहेंगे।

- ट्रेन संख्या 09431/09432 साबरमती-बेगूसराय अनारक्षित स्पेशल ट्रेन विशेष किराए पर (28 फेरे)

ट्रेन संख्या 09431 साबरमती-बेगूसराय अनारक्षित स्पेशल साबरमती से 14 अक्टूबर 2025 से 27 अक्टूबर 2025 तक प्रतिदिन दोपहर 12:05 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन सुबह 08:00 बजे बेगूसराय पहुचेंगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 09432 बेगूसराय-साबरमती अनारक्षित स्पेशल बेगूसराय से 16 अक्टूबर 2025 से 29 अक्टूबर 2025 तक प्रतिदिन दोपहर 12:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन सुबह 05:00 बजे साबरमती पहुचेंगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन महेसाणा, पालनपुर, आबूरोड, फालना, मारवाड़ जं.,ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, दौसा, बाँदीकुई जं., भरतपुर, ईदगाह आगरा, टुंडला, इटावा, गोविंदपुरी, सुबेदारगंज, मिजार्पुर, पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र जं., सोनपुर, हाजीपुर एवं बरौनी जं. स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में सभी अनारक्षित श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में शत प्रतिशत की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की

(जीएनएस)।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत पूर्व सैनिकों (ईएसएम) और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में शत प्रतिशत की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह निर्णय सरकार की पूर्व सैनिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता को दशार्ता है। स्वीकृत बढ़ोतरी इस प्रकार हैं:

पेनुरी ग्रांट को प्रति लाभार्थी 4,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इस कदम से 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे वृद्ध और गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों तथा उनकी वीर नारियों को आजीवन आर्थिक सुरक्षा व निरंतर सहायता सुनिश्चित होगी, जिनकी कोई नियमित आय नहीं है। इसके अलावा, दो आश्रित बच्चों (कक्षा 1 से स्नातक तक) या दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रही वीर नारियों के लिए शिक्षा अनुदान को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति कर दिया गया है, जिससे शिक्षा के अवसरों को और सशक्त सहयोग मिलेगा।

विवाह अनुदान को प्रति लाभार्थी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। यह संशोधित अनुदान पूर्व सैनिकों की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह और वीर नारियों के पुनर्विवाह पर लागू होगा, बशर्ते ये विवाह इस आदेश के जारी होने के बाद संपन्न हुए हों।

संशोधित दरें 1 नवंबर, 2025 से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर लागू होंगी। इन संशोधनों से सरकार पर लगभग 257 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय भार आएगा, जिसे सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) से वहन किया जाएगा।

इन योजनाओं का वित्तपोषण रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष के माध्यम से किया जाता है, जो एएफएफडीएफ का एक उपकोष है और पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों के कल्याण के लिए समर्पित है।

यह निर्णय गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और निम्न आय वर्ग के आश्रितों के लिए सामाजिक सुरक्षा के ताने-बाने को सशक्त बनाता है। साथ ही, यह देश के पूर्व सैनिकों की सेवा, समर्पण एवं बलिदान के प्रति सरकार की अटूट सम्मानभावना और प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम में इंडोनेशिया की नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास 'समुद्र शक्ति'- 2025 के पांचवें संस्करण की मेजबानी करेगी

(जीएनएस)।

भारतीय नौसेना 14 से 17 अक्टूबर 2025 तक विशाखापत्तनम में भारत-इंडोनेशिया संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, 'समुद्र शक्ति- 2025' के पांचवें संस्करण की मेजबानी कर रही है। इस अभ्यास में भाग लेने वाली इकाइयों में आईएनएस कवरत्ती, पूर्वी नौसेना कमान (ईएनसी) के तत्वावधान में पूर्वी बेड़े का एक पनडुब्बी रोधी युद्धक कोर्वेट और इंडोनेशिया की नौसेना का पोत केआरआई जॉन लाइ, एक कोर्वेट (एक अभिन्न हेलीकॉप्टर के साथ) शामिल है। विशाखापत्तनम पहुंचने पर ईएनसी द्वारा इनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

बंदरगाह चरण में सौहार्द और पेशेवर तालमेल बनाने के उद्देश्य से जुड़ी कई गतिविधियों में क्रॉस डेक दौरे, संयुक्त योग सत्र, मैत्रीपूर्ण खेल आयोजन और पेशेवर विषय-वस्तु विशेषज्ञों का आदान-प्रदान (एसएमईई) शामिल हैं। समुद्री चरण में सामरिक समन्वय बढ़ाने के उद्देश्य से गतिशील और जटिल समुद्री अभियान शामिल होंगे, जिनमें हेलीकॉप्टर संचालन, वायु रक्षा अभ्यास, हथियार फायरिंग अभ्यास, दौरा, बोर्ड, खोज और जब्ती (वीबीएसएस) अभ्यास शामिल हैं।

अभ्यास 'समुद्र शक्ति' एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय अभ्यास है जिसका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाना, आपसी समझ को मजबूत करना और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करना है। यह अभ्यास हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दशार्ता है।

यूएनटीसीसी के प्रमुखों ने आगरा में एकीकृत प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन देखा

(जीएनएस)।

भारतीय सेना द्वारा 14 से 16 अक्टूबर, 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों (यूएनटीसीसी) के प्रमुखों का सम्मेलन 2025 आज भी जारी रहा, जिसमें प्रमुखों ने एकीकृत नए युग की प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन देखा।

दिन के मुख्य कार्यक्रम

यूएनटीसीसी प्रमुखों ने आगरा का दौरा किया, जहां उन्होंने एकीकृत आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन देखा, जिसमें भारतीय सेना द्वारा निर्मित नई पीढ़ी के उपकरणों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की गई। इस प्रदर्शन ने भारत के आत्मनिर्भरता पर जोर और शांति स्थापना तथा उससे परे समकालीन संचालन चुनौतियों का सामना करने के लिए आधुनिक, नवीन और किफायती समाधान प्रस्तुत करने की उसकी क्षमता को दशार्या।

प्रतिनिधियों ने दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक, ताजमहल का भी दौरा किया, जो सद्भाव और सार्वभौमिक विरासत का प्रतीक है। इसके बाद, कलाकृति हेरिटेज सेंटर का दौरा किया गया, जहां प्रतिभागियों ने भारत की कलात्मक विरासत और समृद्ध परंपराओं को दशार्ने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा। इस दौरे ने कलाकारों से बातचीत करने और भारत की अनूठी विरासत शिल्पकला को देखने का भी अवसर प्रदान किया।

सांस्कृतिक कार्यक्रम

शाम को, प्रतिनिधि लाल किले में एक प्रकाश एवं ध्वनि शो भी देखेंगे, जो भारत की सभ्यतागत यात्रा और राष्ट्रीय गौरव के मील के पत्थरों का वर्णन करेगा। यूएनटीसीसी प्रमुख दिल्ली मेट्रो से कार्यक्रम स्थल तक जाएंगे, जो आधुनिकता और सतत शहरी आवागमन की दिशा में भारत की यात्रा में एक विश्व स्तरीय तकनीकी उपलब्धि है। यूएनटीसीसी प्रमुख शहरी परिवहन से लेकर सैन्य तैयारियों तक, भारत के तकनीकी प्रयासों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करेंगे, जो प्रगति, सशक्तता और वैश्विक प्रासंगिकता के समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण को दशार्ता है।

कॉन्क्लेव के दूसरे दिन, सांस्कृतिक पहुंच के साथ संचालन संबंधी प्रदर्शन का सफलतापूर्वक सम्मिश्रण किया गया, जिससे एक राष्ट्र के रूप में भारत की भूमिका सुदृढ़ हुई, जो न केवल अपनी सैन्य प्रगति के माध्यम से वैश्विक शांति और स्थायित्व की साझा आकांक्षाओं में योगदान देता है, बल्कि राष्ट्रों के बीच मैत्री के सेतु के रूप में अपनी सभ्यतागत लोकाचार और विरासत को भी प्रस्तुत करता है।

यह सम्मेलन कल अंतिम विचार-विमर्श, उद्योग के साथ बातचीत और परिणामों के सारांश के साथ संपन्न होगा, जिससे मजबूत, समावेशी और टिकाऊ संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए आगे का रास्ता तय होगा।

इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित 16वीं डब्ल्यू एच ओ-आई आर सी एच वार्षिक बैठक में भारत ने हर्बल औषधि विनियमन में अपनी अग्रणी भूमिका प्रदर्शित की

(जीएनएस)।

विश्व स्वास्थ्य संगठन - अंतर्राष्ट्रीय हर्बल औषधि नियामक सहयोग (डब्ल्यू एच ओ-आई आर सी एच) की 16वीं वार्षिक बैठक 14 से 16 अक्टूबर 2025 तक इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित की जा रही है। इस आयोजन में हर्बल औषधियों के विनियमन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामंजस्य को सुदृढ़ करने के उद्देश य से विश वभर के विनियामक प्राधिकरणों और विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया है।

भारत ने इस बैठक में उल लेखनीय योगदान दिया, जिसमें डॉ. रघु अरक्कल, सलाहकार (आयुर्वेद) और उप महानिदेशक (प्रभारी), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सक्रिया भागीदारी की। इस प्रतिनिधिमंडल ने कार्यक्रम के दूसरे दिन आयोजित तकनीकी सत्रों में प्रमुख भूमिका निभाई।

डॉ. रघु अरकल ने "हर्बल औषधियों की प्रभावकारिता और इच्छित उपयोग (कार्य समूह-3)" पर कार्यशाला रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें

पारंपरिक चिकित्सा में भारत के विकसित होते विनियामक ढाँचे और साक्ष्य-आधारित नीतिगत पहलों पर प्रकाश डाला गया।

भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी फामाकीपिया आयोग (पीसीआईएमएंडएच) के निदेशक डॉ. रमन मोहन सिंह ने "हर्बल औषधियों की सुरक्षा और विनियमन (कार्य समूह-1)" पर कार्यशाला रिपोर्ट प्रस्तुत की और "हर्बल औषधियों की सुरक्षा और विनियमन - भारतीय परिप्रेक्ष्य" पर एक अलग प्रस्तुति भी दी।

दोनों कार्यशालाएँ विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गईं और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा पीसीआईएमएंडएच के सहयोग से उनकी मेजबानी की गई थी। ये कार्यशालाएँ 6 से 8 अगस्त 2025 तक गाजियाबाद में आयोजित की गईं और विश्व स्वास्थ्य संगठन-आईआरसीएच बैठक के लिए प्रमुख प्रारंभिक जानकारी के रूप में कार्य किया।

इसके अलावा, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेश दाधीच ने डॉ. सिंह के साथ मिलकर "हर्बल औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण, मानकीकरण और सततता" पर एक सत्र का सह-प्रस्तुतिकरण किया। डॉ. दाधीच ने औषधीय पौधों के सतत उपयोग और गुणवत्ता नियंत्रण व मानकीकरण सुनिश्चित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर भी विचार साझा किए।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का व्यापक योगदान हर्बल औषधियों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता के वैश्विक मानकों को आकार देने में भारत की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करता है। डब्ल्यू एच ओ-आई आर सी एच के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय विनियामक निकायों के साथ सक्रिय सहयोग के माध्यम से भारत पारंपरिक चिकित्सा और प्राकृतिक उत्पाद-आधारित स्वास्थ्य सेवा में विज्ञान-आधारित एवं सामन्जस्यपूर्ण विनियमन को बढ़ावा देता आ रहा है।

भारत की यह भागीदारी हर्बल औषधि विनियमन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने और वैश्विक मानकों को आगे बढ़ाने के लिए उसकी निरंतर प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करती है।

कानालुस-पोरबंदर -कानालुस लोकल ट्रेनें 30 नवंबर तक प्रभावित रहेंगी

राजकोट मंडल के लाखाबावल-पीपली-कानालुस सेक्शन में चल रहे डबलिंग कार्य के कारण 30 नवंबर, 2025 तक कानालुस-पोरबंदर और पोरबंदर-कानालुस लोकल ट्रेनों का परिचालन आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार, प्रभावित ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:

आंशिक रूप से निरस्त की गई ट्रेनें

- ट्रेन संख्या 59206 पोरबंदर-कानालुस लोकल

यह ट्रेन 16 अक्टूबर से 30 नवंबर, 2025 तक पोरबंदर से प्रस्थान कर गोपजाम तक चलेगी तथा गोपजाम-कानालुस खंड के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

- ट्रेन संख्या 59205 कानालुस-पोरबंदर लोकल

यह ट्रेन 16 अक्टूबर से 30 नवंबर, 2025 तक कानालुस की बजाय गोपजाम स्टेशन से चलेगी और कानालुस-गोपजाम खंड के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

यात्रियों से निवेदन

रेल यात्रियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं। ट्रेनों के परिचालन से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए यात्री वेबसाइट www. enquiry. indianrail. gov.in पर अवलोकन करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में 'गुजरात@75 : एजेंडा फॉर 2035' का अनावरण किया

राज्य सरकार ने 2035 में गुजरात राज्य की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अगले दशक के लिए विकास एजेंडा प्रस्तुत किया

- गुजरात सरकार के एजेंडा में 4 आई- इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन्स शामिल
- गुजरात@75 : 7500 स्कूलों में एआई-आधारित शिक्षा, 75 एडवांस्ड स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना और 75 लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य
- राज्य सरकार अगले एक दशक में 7.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर सड़क, सिंचाई, बंदरगाह, परिवहन, जल और ऊर्जा आपूर्ति में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाएगी

गांधीनगर, 15 अक्टूबर : गुजरात राज्य वर्ष 2035 में अपनी स्थापना के ऐतिहासिक 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है। ऐसे में, गुजरात सरकार ने राज्य के लिए अगले एक दशक में विकास की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए 'गुजरात@75 : एजेंडा फॉर 2035' दस्तावेज का अनावरण किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में इस दस्तावेज का अनावरण किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि यह मील का पत्थर गुजरात की उपलब्धियों का जश्न मनाने के साथ ही भविष्य के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को भी व्यक्त करता है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए 'विकसित भारत@2047' के विजन के अनुरूप है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एजेंडा आगामी दशक में गुजरात के प्रत्येक व्यक्ति के लिए 'अर्निंग वेल, लिविंग वेल' यानी 'बेहतर कमाई, बेहतर जीवन' का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में सरकार के प्रयासों की समीक्षा करेगा।

'समृद्ध राज्य, समर्थ नागरिक' के सूत्र को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है गुजरात सरकार

'एजेंडा फॉर 2035' दस्तावेज में गुजरात की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर राज्य के लक्ष्यों और उसे हासिल करने के लिए बनाई गई रणनीतियों का उल्लेख किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, बुनियादी ढांचा विकास और पर्यावरणीय स्थिरता आदि क्षेत्रों को गति देना और राज्य के सभी जिलों में संतुलित एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। यह सरकार की 'समृद्ध राज्य, समर्थ नागरिक' सूत्र को साकार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

गुजरात@75 : 7500 स्कूलों में एआई-आधारित शिक्षा, 75 एडवांस्ड स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना और 75 लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य

राज्य के शिक्षित और कुशल युवा गुजरात के विकास का मुख्य स्तंभ हैं, इसलिए राज्य उन्हें सशक्त करने पर बल देगा। वर्ष 2035 तक गुजरात के प्रत्येक बच्चे को आधुनिक और भविष्य-उन्मुख शिक्षा की सुविधा मिलेगी। 7500 स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई-आधारित शिक्षा शुरू की जाएगी और 75 एडवांस्ड स्किल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे, जिससे 75 लाख नौकरियां सृजित होंगी।

राज्य का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाना, एक व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य नेटवर्क स्थापित करना और प्रत्येक परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज सुनिश्चित करना है। ये कदम गुजरात के स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे।

स्वच्छ ऊर्जा और हरित भविष्य को बढ़ावा देने का लक्ष्य

गुजरात स्वच्छ ऊर्जा और हरित भविष्य को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। गुजरात अगले 10 वर्षों में 750 स्थानों को हरित बनाकर उन्हें अर्बन लंग्स के रूप में विकसित करेगा। राज्य में 7500 मियावाकी जंगल बनाए जाएंगे, 75 फीसदी म्युनिसिपल अपशिष्ट जल को रिसाइकिल किया जाएगा और 75 आइकॉनिक इमारतों का निर्माण भी किया जाएगा। डिजिटल गवर्नेंस और ई-सेवाएं हर नागरिक को सशक्त बनाएंगी।

समृद्ध किसान और ग्रामीण विकास : फसल की गुणवत्ता में सुधार, मूल्यवर्धन और कृषि-प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों की आय बढ़ेगी, जो ग्रामीण समृद्धि को गति देगी।

गुजरात का लक्ष्य ग्रीन एनर्जी और नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने में अग्रणी राज्य बनना है। राज्य का लक्ष्य अगले दशक में ग्रीन एनर्जी संचालित करना है, जिसमें हाइड्रोजन प्लांट, 75 गीगावाट पवन ऊर्जा, 7500 इलेक्ट्रिक बसें और सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह न केवल टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन देगा, बल्कि हजारों रोजगार का सृजन भी करेगा।

गुजरात नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करेगा : गुजरात 2035 तक नवाचार और उद्यमिता के नए आयाम स्थापित कर, स्टार्टअप्स और उद्यमों को बढ़ावा देकर भारत का इनोवेशन पावरहाउस बनेगा।

मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से राज्य नई बुलंदियों को छुएगा : गुजरात 7.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ सड़क, सिंचाई, बंदरगाह, परिवहन, जल और ऊर्जा आपूर्ति में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाएगा।

4 आई- इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन्स

गुजरात की यह योजना- '4 आई' यानी इंफ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचा), इनोवेशन (नवाचार), इंडिविजुअल्स (व्यक्तियों) और इंस्टीट्यूशन्स (संस्थानों) पर ध्यान केंद्रित करती है। 2035 के लिए एजेंडा अगले एक दशक में नीतियों और उनके क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट एवं परिणामोन्मुखी मार्गदर्शन प्रदान करता है।

गुजरात सरकार के लिए यह दस्तावेज गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (जीआरआईटी-ग्रिट) की ओर से तैयार किया गया है, जिसमें गुजरात सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सोसाइटी (जीएसआईडीएस), गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (जीआईडीबी), गुजरात स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन हब (आई-हब), उच्च शिक्षा विभाग और योजना तथा प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण प्रभाग (एआरटीडी) जैसे सरकारी विभाग, संस्थानों और बोर्ड की सक्रिय भागीदारी है।

'गुजरात@75 : एजेंडा फॉर 2035' का अनावरण 2047 तक गुजरात को विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। यह भारत में विकास और नवाचार को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाएगा।

तीन नई डॉ. अंबेडकर पीठों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन

(जीएनएस)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन ने तीन विश्वविद्यालयों; मुंबई विश्वविद्यालय, जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और जीबी पंथ तकनीकी विश्वविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय में तीन नई डॉ. अंबेडकर पीठों की स्थापना के लिए 15 अक्टूबर, 2025 को डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (डीएआईसी), नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह का आयोजन किया।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने की। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव श्री अमित यादव, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन के प्रतिनिधि और प्रतिभागी विश्वविद्यालयों के कुलपति भी इस समारोह में उपस्थित थे।

इस अवसर पर अपने संबोधन में, डॉ. वीरेंद्र कुमार ने शैक्षणिक और शोध पहलों के माध्यम से भारत रत्न डॉ. बी.आर. अंबेडकर की विचारधारा और दृष्टिकोण के प्रसार में डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन के निरंतर प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और संस्थागत सहयोग, डॉ. अंबेडकर की परिकल्पना के अनुसार एक समतामूलक और समावेशी समाज के निर्माण के सबसे सशक्त साधन हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नव स्थापित पीठें सामाजिक न्याय, समानता, वंचित समुदायों के सशक्तिकरण और संवैधानिक मूल्यों से संबंधित मुद्दों पर नीति-उन्मुख अनुसंधान, जन जागरूकता और अकादमिक विमर्श में सार्थक योगदान देंगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव ने अपने संबोधन में डॉ. आंबेडकर के दर्शन और समकालीन सामाजिक एवं कानूनी चुनौतियों में उनकी प्रासंगिकता पर बहु-विषयक शोध को बढ़ावा देने में विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने 'अंबेडकरवादी' विचारधारा पर शैक्षणिक जुड़ाव को मजबूत करने में फाउंडेशन और विश्वविद्यालयों के सहयोगात्मक दृष्टिकोण की सराहना की।

नए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर के साथ, वर्तमान नेटवर्क में तीन अतिरिक्त डॉ. अंबेडकर पीठें जुड़ गई हैं, जिससे इस योजना के अंतर्गत कार्यरत पीठों की कुल संख्या अट्ठाईस हो गई है। भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने मंत्रालय के प्रति आभार व्यक्त किया और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान एवं आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से योजना के उद्देश्यों को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया।

कार्यक्रम का समापन डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन के निदेशक द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ। उन्होंने माननीय मंत्री महोदय डॉ. वीरेंद्र कुमार, सचिव, मंत्रालय के अधिकारियों और विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों को उनके समर्थन और भागीदारी के प्रति हार्दिक सराहना व्यक्त की।

डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन ने इस पहल का विस्तार जारी रखने के अपने संकल्प की पुनः पुष्टि की, ताकि भारत भर के शैक्षणिक संस्थान डॉ. अंबेडकर के जीवन और दर्शन से प्रेरित होकर अनुसंधान, नीति विकास और सार्वजनिक शिक्षा के लिए उत्कृष्टता के केंद्र बन सकें।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) मासिक बुलेटिन, सितंबर 2025

ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल भागीदार दर में वृद्धि ने लगातार तीसरे महीने समग्र महिला श्रम बल भागीदार दर में सुधार किया

ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल प्रतिशतता (डब्ल्यूपीआर) में निरंतर वृद्धि आर्थिक समावेशन में मजबूती का संकेत देती है

(जीएनएस)।

श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में वृद्धि का रुझान जारी है। सितंबर 2025 में कुल श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 5 महीने के उच्चतम स्तर 55.3 प्रतिशत पर पहुंच गई।

श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। सितंबर 2025 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं में श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 34.1 प्रतिशत थी और यह मई 2025 के बाद से महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) का उच्चतम स्तर था।

सितंबर 2025 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में कुल श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्‍ ल्‍ यूपीआर) 52.4 प्रतिशत दर्ज किया गया, जो मई 2025 के बाद से उच्चतम स्तर था।

15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं में कुल श्रम बल भागीदारी दर (डब्‍ ल्‍ यूपीआर) लगातार तीसरे महीने लगातार बढ़ी है।

पिछले दो लगातार महीनों के दौरान गिरावट के बाद, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में बेरोजगारी दर (यूआर) अगस्त 2025 में दर्ज 5.1 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर सितंबर 2025 में 5.2 प्रतिशत हो गई।

परिचय

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संचालित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) जनसंख्या की गतिविधि भागीदारी और रोजगार-बेरोजगारी की स्थिति के आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है। देश के श्रम बल संकेतकों के मासिक और त्रैमासिक अनुमान प्रदान करने के लिए पीएलएफएस सर्वेक्षण पद्धति को जनवरी 2025 से संशोधित किया गया है।

पीएलएफएस के मासिक परिणाम मासिक बुलेटिन के रूप में जारी किए जाते हैं। यह वर्तमान साप्ताहिक स्थिति[1] (सीडब्ल्यूएस) दृष्टिकोण के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर प्रमुख श्रम बाजार संकेतकों जैसे श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) के अनुमान प्रस्तुत करता है।

अप्रैल 2025 से अगस्त 2025 तक के मासिक बुलेटिन पहले ही जारी किए जा चुके हैं। सितंबर 2025 माह का वर्तमान मासिक बुलेटिन इस श्रृंखला का छठा बुलेटिन है।

वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) के बाद 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए मुख्य निष्कर्षः

श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में वृद्धि का रुझान जारी हैः

15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच समग्र एलएफपीआर में लगातार तीसरे महीने वृद्धि जारी रही और यह जून 2025 में 54.2 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2025 में 55.3 प्रतिशत हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में एलएफपीआर भी जून 2025 में 56.1 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2025 में 57.4 प्रतिशत हो गई है। शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए एलएफपीआर अगस्त 2025 की तुलना में 50.9 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही है।

सितंबर 2025 में समग्र एलएफपीआर 5 महीने के उच्चतम स्तर 55.3 प्रतिशत पर पहुंच गया

श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही हैः सितंबर 2025 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं में समग्र एलएफपीआर 34.1 प्रतिशत थी और यह मई 2025 के बाद से महिला एलएफपीआर का उच्चतम स्तर था। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एलएफपीआर में वृद्धि का योगदान था।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की लायंस क्लब के अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ गांधीनगर में बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छता से सेमीकंडक्टर तक सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सकारात्मक नेतृत्व के फलस्वरूप भारत की ग्लोबल इमेज में वृद्धि हुई है
- प्रधानमंत्री की 'वसुधैव कुटुम्बकम्' तथा 'सबका साथ-सबका विकास' की राजनीति से विश्व के देशों में भारत के प्रति विश्वास दृढ़ हुआ है

गांधीनगर, 15 अक्टूबर : लायंस क्लब इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों ने बुधवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से भेंट की।

मुख्यमंत्री ने अपनी अध्यक्षता में आयोजित इस मुलाकात-बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने

स्वच्छता से लेकर सेमीकंडक्टर तक सभी क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी है। इसके फलस्वरूप देश विकास के नित-नए शिखर पार कर रहा है।

श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सकारात्मक नेतृत्व के परिणामस्वरूप भारत की ग्लोबल इमेज में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' तथा 'सबका साथ-सबका विकास' की जो राजनीति दी है, उससे विश्व के देशों में भारत के प्रति विश्वास बढ़ा है।

मुख्यमंत्री ने लायंस क्लब की विश्वभर के देशों में सेवाभावी संस्था के रूप में उपस्थिति की प्रशंसा की और संस्था को उसके विकासोन्मुखी कार्यों में राज्य सरकार के उचित सहयोग का भी आश्वासन दिया।

उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू कराए गए अभियानों से आ रहे परिवर्तनों की भूमिका दी और लायंस क्लब द्वारा सरकार के अभियानों में सक्रिय भागीदारी की भी सराहना की।

इस अवसर पर लायंस क्लब के इंटरनेशनल प्रेसीडेंट श्री ए. पी. सिंह, अन्य पदाधिकारी तथा सदस्य उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री श्री रैला ओडिंगा के निधन पर शोक व्यक्त किया

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री श्री रैला ओडिंगा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है "मेरे प्रिय मित्र और केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री श्री रैला ओडिंगा के निधन से मुझे गहरा दुःख हुआ है। वह एक प्रखर राजनेता और भारत के प्रिय मित्र थे। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मुझे उन्हें करीब से जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारा सहयोग वर्षों तक कायम रहा।" श्री मोदी ने यह भी कहा कि श्री रैला ओडिंगा का भारत की संस्कृति, मूल्यों और हमारे प्राचीन ज्ञान के प्रति विशेष लगाव था और यह भारत-केन्या सम्‍ बंधों को मजबूत करने के उनके प्रयासों में परिलक्षित होता था।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:

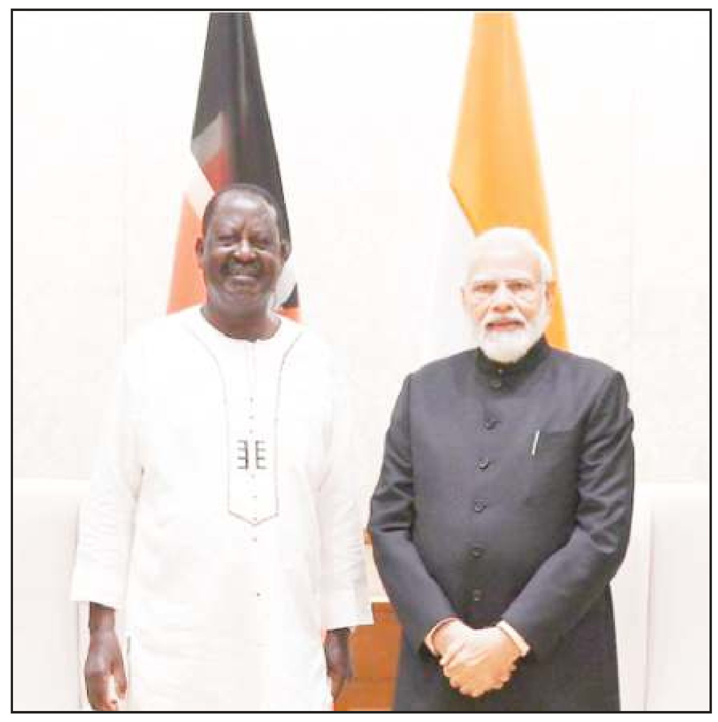

"मेरे प्रिय मित्र और केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री, श्री रैला ओडिंगा के निधन से मुझे गहरा दुःख हुआ है। वे एक प्रखर राजनेता और भारत के प्रिय मित्र थे। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मुझे उन्हें करीब से जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारा सहयोग वर्षों तक कायम रहा। भारत की संस्कृति, मूल्यों और प्राचीन ज्ञान के प्रति उनका विशेष लगाव था। यह भारत-केन्या सम्‍ बंधों को मजबूत करने के उनके प्रयासों में परिलक्षित होता था। वे विशेष रूप से भारत की आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रशंसक थे, उन्होंने अपनी बेटी के स्वास्थ्य लाभ में इनके सकारात्मक प्रभाव को देखा था। इस दुःख की घड़ी में मैं उनके परिवार, मित्रों और केन्या के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।"

केंद्रीय मंत्री ने निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी के साथ नवाचार-संचालित अर्थव्यवस्था का आह्वान किया

सीएसआईआर-एनआईआईएसटी तिरुवनंतपुरम के स्वर्ण जयंती समारोह में विज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्मरण किया कि इस संस्थान की परिकल्पना 50 साल पहले दक्षिणी प्रायद्वीप के विशाल प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक प्रगति के लिए दोहन करने के उद्देश्य से की गई थी

डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के ज्ञान-संपदा को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान प्रयोगशालाओं को स्टार्टअप हब में बदलने पर जोर दिया

डॉ. जितेंद्र सिंह ने अंतःविषयक और अंतर-सरकारी दृष्टिकोण के एकीकरण से तालमेल को मजबूत करने पर बल दिया

आयुर्वेद और सतत बहुलक के लिए नए केंद्र भारत के हरित और आत्मनिर्भर अनुसंधान भविष्य को देंगे आधार

प्रविष्टि तिथिः 15 डउळ 2025 4:03ढट ु८ ढक्ह ऊँ

निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी के साथ नवाचार-संचालित अर्थव्यवस्था का मजबूत समर्थन करते हुए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि भारत का प्रौद्योगिकी आयातक से नवाचार-संचालित निर्यातक बनने का मार्ग सीएसआईआर-राष्ट्रीय अंतःविषयक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईआईएसटी) जैसे संस्थानों द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान को सततता और उद्यमिता के साथ जोड़ते हैं।

तिरुवनंतपुरम में सीएसआईआर-एनआईआईएसटी के स्वर्ण जयंती माइलस्टोन ऑब्जर्वेशन कार्यक्रम के समापन समारोह में बोलते हुए मंत्री महोदय ने स्मरण किया कि 50 वर्ष पहले इस संस्थान की परिकल्पना दक्षिणी प्रायद्वीप के विशाल प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक प्रगति के लिए दोहन करने के उद्देश्य से की गई थी।

संस्थान की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डॉ. जितेंद्र सिंह ने नए स्वर्ण जयंती भवन और सीएसआईआर-एनआईआईएसटी नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया, जिसे अनुसंधान विचारों को व्यवहार्य उत्पादों और स्टार्टअप में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। उन्होंने कहा, "कृषि से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक यह नवाचार केंद्र स्टार्टअप को पोषित करेगा, उद्यमियों का समर्थन करेगा और नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।" उन्होंने यह भी बताया कि दस स्टार्टअप का पहला

समूह पहले ही इनक्यूबेशन पूरा कर चुका है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने सूचित किया कि केरल सरकार ने बायो 360 लाइफ साइंसेज पार्क के भीतर प्रस्तावित नवाचार, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता केंद्र के लिए थोंनाक्कल में भूमि आवंटित की है। उन्होंने आगे कहा, "यह सुविधा जैव प्रौद्योगिकी और जीव विज्ञान में अनुप्रयुक्त अनुसंधान को गति प्रदान करेगी और प्रयोगशाला की सफलताओं को जीवन-परिवर्तनकारी वास्तविकताओं में बदलेगी।"

संस्थान की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय महत्व के चार नवाचारों का उल्लेख किया - एम्स, दिल्ली में स्थापित एक जैव-चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण रिग जो संक्रामक अपशिष्ट को गैर-विषाक्त पदार्थ में परिवर्तित करता है; मधुमेह और पूर्व-मधुमेह रोगियों के लिए उपयुक्त "डिजाइनर चावल" का विकास; आयात निर्भरता को कम करने के लिए स्वदेशी वैक्सीन वायल मॉनिटर (वीवीएम) और प्लास्टिक के टिकाऊ पैकेजिंग विकल्पों पर अनुसंधान। उन्होंने कहा, "ये पहलें सामाजिक प्रभाव वाले विज्ञान को दशार्ती हैं," और जोड़ा कि ऐसी प्रौद्योगिकियाँ स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत और आत्मनिर्भर भारत जैसे राष्ट्रीय मिशनों को सीधे समर्थन प्रदान करती हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह, जो सीएसआईआर के उपाध्यक्ष भी हैं, ने अपेक्षाकृत छोटा संस्थान होने के बावजूद एनआईआईएसटी के प्रदर्शन की सराहना की। पिछले दो वर्षों में इसका संस्थागत बजट डेढ़ गुना बढ़कर 120 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जिसका आधा हिस्सा अनुसंधान एवं विकास पर खर्च किया गया है। प्रयोगशाला ने 28 प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण किया है, 65 उद्योग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और बाहरी वित्तपोषण एवं अनुसंधान उत्पादन के रिकॉर्ड स्तर हासिल किए हैं, जिसे मंत्री महोदय ने "उद्देश्यपूर्ण उत्कृष्टता" की संज्ञा दी।

मंत्री महोदय ने 2024 में आईआईटी गुवाहाटी में 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के आयोजन में संस्थान की अग्रणीय भूमिका को याद किया, जिसमें 40,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। उन्होंने कहा, "देश के दक्षिणी छोर से लेकर उत्तर पूर्व तक इस तरह के एक बड़े आयोजन की मेजबानी सीएसआईआर-एनआईआईएसटी की एकता और नेतृत्व को दशार्ती है।"

सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित "संपूर्ण सरकार" और "संपूर्ण राष्ट्र" का दृष्टिकोण भारत की वैज्ञानिक प्रगति की कुंजी है। उन्होंने कहा, "हमें सरकारी निर्भरता से हटकर निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी के साथ आत्मनिर्भर इको-सिस्टम की ओर बढ़ना चाहिए।" उन्होंने मंत्रालयों और वैज्ञानिक संस्थानों के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया और इसे "अंतःविषयक" तथा "अंतर-सरकारी" दृष्टिकोण का एकीकरण बताया।

सीएसआईआर और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के बीच चल रहे सहयोग और अंतरिक्ष तथा परमाणु क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के निर्णय का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह एकीकृत मॉडल भारत के नवाचार ढांचे के भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है।

विज्ञान को राष्ट्रीय विकास की कहानी से जोड़ते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग 2014 में 81 से बढ़कर इस वर्ष 38 हो गई है, जो विश्व के प्रमुख नवाचार प्रदर्शनकारियों में भारत के उदय का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भारत से दायर लगभग 55 प्रतिशत पेटेंट अब रेजिडेंट पेटेंट हैं, जो बढ़ती घरेलू क्षमता और आत्मविश्वास को रेखांकित करता है। बढ़ते अनुसंधान एवं विकास निवेश और उद्योगिक भागीदारी के साथ भारत के वैज्ञानिक संस्थान अब सतत विकास और नवाचार-आधारित आर्थिक मजबूती के प्रमुख योगदानकर्ता बनने के लिए तैयार हैं।

मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि सीएसआईआर-एनआईआईएसटी ने दो उत्कृष्टता केंद्रों की नींव रखी है - एक आयुर्वेद अनुसंधान में और दूसरा परफॉरमेंस केमिकल एवं सतत बहुलक में - जो पारंपरिक चिकित्सा में केरल की विरासत और हरित प्रौद्योगिकियों पर भारत के फोकस को दशार्ता है। उन्होंने कहा कि नवाचार केंद्र "अवधारणा से व्यावसायीकरण" के विजन का प्रतीक है, यह सुनिश्चित करता है कि अनुसंधान लोगों और उद्योग दोनों के लिए ठोस लाभों में परिवर्तित हो। उन्होंने आगे कहा कि ये पहलें पोषण अभियान, स्वच्छ भारत और आत्मनिर्भर भारत जैसे राष्ट्रीय मिशनों के अनुरूप हैं और संस्थान को भारत के नवाचार इको-सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग बनाती हैं।

सतत प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने और उद्योगिक रूपांतरण को सक्षम करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 और